

II. समग्र मांग*

2012-13 की ति2 के दौरान अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति मंद बनी रही। निजी उपभोग, जो कि समग्र मांग का मुख्य आधार होता है, में कमी आना जारी रहा जो कि उच्च मुद्रास्फीति के प्रभाव को दर्शाता है। किंतु वर्ष की पहली छमाही के दौरान सरकारी उपभोग में वृद्धि हुई। अनुमान के अनुसार अब राजकोषीय सुधार हो रहा है जिससे मांग के प्रबंध में सुधार होने की संभावना है। सब्सिडी को नियंत्रित रखने के लिए किए जा रहे उपायों को जारी रखने और तेजी से करने की आवश्यकता

है ताकि राजकोषीय असंतुलन में कमी आए और संसाधन मुक्त हो जाए जिससे अगले वर्ष पूंजीगत व्यय बढ़ाया जा सकेगा। 2012-13 की ति2 में निवेश में कुछ क्रमिक वृद्धि हुई थी जैसा कि तिमाही के दौरान सकल नियत पूंजी निर्माण में कुछ वृद्धि और स्वीकृत परियोजना सहायता से देखा जा सकता है। निवेश चक्र में सुधार, जो कि दो वर्षों से अधोमुखी रहा है, सरकारी निवेश और निजी निवेश में वृद्धि के साथ ही बिजली तथा सड़क क्षेत्र की बाधाओं के समाधान पर निर्भर करता है।

जीडीपी का व्यय पक्ष निरंतर दुर्बल मांग दर्शाता रहा

II.1 बाजार मूल्य पर जीडीपी की वृद्धि 2012-13 की ति2 में तेजी से कम होकर 2.8 प्रतिशत के 13 तिमाहियों के

सारणी II.1 : जीडीपी का व्यय पक्ष (2004-05 के मूल्यों पर)

(प्रतिशत)

मद	2010-11*	2011-12#	2011-12				2012-13		2011-12	2012-13
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	छमाही I	छमाही I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वृद्धि दरें										
बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी	9.6	6.9	9.0	6.9	6.2	5.6	3.9	2.8	7.9	3.4
कुल खपत व्यय	8.1	5.4	4.9	4.9	6.1	5.8	4.7	4.4	4.9	4.6
(i) निजी	8.1	5.5	4.9	4.6	6.4	6.1	4.0	3.7	4.7	3.8
(ii) सरकारी	7.8	5.1	4.9	7.2	4.7	4.1	9.0	8.7	6.0	8.8
सकल अचल पूंजी निर्माण	7.5	5.5	14.7	5.0	-0.3	3.6	0.7	4.1	9.7	2.3
स्टॉक में परिवर्तन	37.4	2.4	7.1	2.8	0.4	-0.4	-1.2	-0.1	5.0	-0.7
मूल्यवान वस्तुएं	32.4	7.9	9.8	9.4	2.9	9.3	-55.4	-27.9	9.6	-41.5
निवल निर्यात	5.5	-30.7	-23.2	-46.7	-117.9	117.8	-2.1	-11.6	-35.5	-7.5
विसंगतियां	38.9	-112.7	-51.8	-119.6	-152.0	-124.0	-123.7	51.1	-88.0	-276.3
सापेक्षिक हिस्सा										
कुल खपत व्यय	70.1	69.1	70.1	70.8	72.7	63.6	70.6	71.9	70.4	71.3
(i) निजी	58.7	57.9	59.5	60.3	60.4	52.2	59.5	60.8	59.9	60.2
(ii) सरकारी	11.4	11.2	10.6	10.5	12.3	11.4	11.1	11.1	10.5	11.1
सकल अचल पूंजी निर्माण	32.5	32.0	33.9	33.4	30.3	30.9	32.8	33.8	33.6	33.3
स्टॉक में परिवर्तन	3.7	3.5	3.7	3.6	3.4	3.4	3.5	3.5	3.7	3.5
मूल्यवान वस्तुएं	2.4	2.4	2.6	2.7	2.1	2.2	1.1	1.9	2.7	1.5
निवल निर्यात	-6.0	-7.3	-8.6	-11.3	-11.1	0.6	-8.5	-12.3	-10.0	-10.4
विसंगतियां	-2.5	0.3	-1.7	0.8	2.6	-0.6	0.4	1.2	-0.4	0.8
ज्ञापन:										
बाजार मूल्य पर वास्तविक जीडीपी (रुपये बिलियन में)	52,368	55,959	13,174	13,111	14,377	15,296	13,693	13,480	26,285	27,173

*: त्वरित अनुमान।

#: संशोधित अनुमान।

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।

* उनकी भलीभाँति विदित सीमाओं के बावजूद व्यय-पक्ष के जीडीपी आंकड़ों को कुल मांग के घटकों के लिए प्रतिनिधि के रूप में प्रयोग किया जाता है।

सारणी II.2 जीडीपी के व्यय पक्ष की योगदान-भारित वृद्धि दरें (2004-05 के मूल्यों पर)*

(प्रतिशत)

	2011-12				2012-13	
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2
1	2	3	4	5	6	7
1. निजी अंतिम खपत व्यय	3.0	2.8	3.9	3.2	2.4	2.2
2. सरकारी अंतिम खपत व्यय	0.5	0.8	0.6	0.5	1.0	0.9
3. सकल अचल पूंजी निर्माण	4.7	1.7	-0.1	1.1	0.2	1.4
4. स्टॉक में परिवर्तन	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
5. मूल्यवान वस्तुएं	0.3	0.2	0.1	0.2	-1.5	-0.8
6. निवल निर्यात (i + ii)	-1.8	-3.8	-6.4	4.0	-0.2	-1.3
(i) निर्यात	3.9	4.4	1.5	4.6	2.4	1.1
(ii) आयात	5.7	8.2	7.9	0.6	2.6	2.4
7. योग (1 to 6)	7.0	1.8	-2.0	9.0	1.9	2.4
8. विसंगतियां	2.0	5.1	8.2	-3.4	2.1	0.4
9. बाजार मूल्य पर जीडीपी (7+8)	9.0	6.9	6.2	5.6	3.9	2.8

*: जीडीपी के व्यय पक्ष के घटक की योगदान-भारित वृद्धि दरें इस प्रकार हैं: (घटक में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन ÷ स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन) × स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दरें।

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।

निम्नतम स्तर पर पहुंच गई जो कि 2011-12 की इसी अवधि में 6.9 प्रतिशत थी (सारणी II.1)। यद्यपि निजी अंतिम उपभोग व्यय वृद्धि का प्रमुख प्रेरक बना हुआ है, वृद्धि में इसका योगदान 2011-12 की ति4 से कम हो गया है (सारणी II.2)।

II.2 2012-13 की पहली छमाही के दौरान बाजार मूल्य पर जीडीपी की वृद्धि कारक लागत वृद्धि की तुलना में काफी कम थी जिसका कारण निवल परोक्ष करों में कम वृद्धि होना था। यह गिरावट सरकारी अंतिम उपभोग व्यय को छोड़कर अन्य सभी घटकों में दिखी। 2012-13 के दौरान अब तक कम आय वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति के कारण निजी उपभोग वृद्धि में कमी आई। निवल निर्यात वृद्धि निरंतर ऋणात्मक बनी रही जिसका आंशिक कारण दुर्बल बाह्य मांग थी। यह बात 2012-13 की ति2 के दौरान हुए चालू खाते के व्यापक घाटे के अनुरूप ही थी।

II.3 आगे, मुद्रास्फीति में संभाव्य कमी आने से निजी अंतिम उपभोग को सहायता मिलेगी। राजकोषीय समेकन संबंधी घोषित उपायों से सरकारी अंतिम उपभोग कुछ नियंत्रित रहेगा। सकल नियत पूंजी निर्माण में तेजी के अधिक निर्णायक संकेत अब तक नहीं दिखे हैं। कुल मिलाकर, 2012-13 के दौरान वृद्धि की प्रक्रिया निजी उपभोग से प्रेरित रहेगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याएं निवेश में बाधा बनी हुई हैं

II.4 1 नवंबर 2012 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र की 563 परियोजनाओं (₹1.5 बिलियन और अधिक), जो कि मुख्यतः पांच क्षेत्रों, नामतः सड़क परिवहन और राजमार्ग, बिजली, पेट्रोलियम, रेलवे और कोयला में संकेंद्रित हैं, में से लगभग आधी के संबंध में विलंब की सूचना मिली। इसके परिणामस्वरूप, इनमें से काफी परियोजनाओं में लागत में व्यापक वृद्धि हुई। विलंब के प्रमुख कारणों में भूमि अधिग्रहण/पर्यावरणीय अनुमति मिलने/परियोजना वित्तपोषण समझौते/इंजीनियरिंग डिजाइन को अंतिम रूप देने में विलंब, इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता और लिकेज की कमी, अवसरों में परिवर्तन और अन्य संविदात्मक मामले शामिल हैं। बिजली और सड़क परिवहन तथा राजमार्ग जैसे दो प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में सर्वाधिक विलंब हुआ।

II.5 सरकार के संकेंद्रित प्रयासों के बावजूद बिजली क्षेत्र की समस्याओं का पूरा समाधान नहीं हुआ है। कोयला लिकेज मामले में, जहां बिजली उत्पादकों ने ईंधन की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ नए करार करना शुरू किया है,

जो कि देशी स्रोतों से 65 प्रतिशत की आश्वस्त आपूर्ति और 15 प्रतिशत की आयातित कोयले से आपूर्ति करता है, वहीं प्राइस पूलिंग के मुख्य मामले का समाधान नहीं हुआ है। देशी और विदेशी कोयले के मूल्य के बीच के व्यापक अंतर को देखते हुए यह आवश्यक है कि आयात के माध्यम से मांग-आपूर्ति के बीच के अंतर को पाटने के लिए प्राइस पूलिंग पर समझौता होना आवश्यक है। इसके अलावा, इस संबंध में राज्य सरकारों से समाधान के लिए कोई पुनर्निर्धारण पैकेज नहीं आ रहा है। राज्य सरकारों और उनके राज्य बिजली बोर्डों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने ऋण को सभी संबंधित जरूरतों के साथ पुनर्निर्धारित करने के लिए स्वयं को तुरंत प्रतिबद्ध कर लें।

II.6 सड़क क्षेत्र में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2011-12 में 6,491 कि.मी. की सड़क परियोजनाओं

के प्रस्ताव के बावजूद इस क्षेत्र में घटते निवेश को नहीं रोका जा सका क्योंकि इनमें से अनेक परियोजनाओं को पर्यावरणीय अनुमति नहीं मिली। कुछ परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण की समस्या में उलझ गईं। इसके अलावा, इन परियोजनाओं से संबद्ध संस्थाओं को वित्तीय कमी का सामना करना पड़ रहा है। नई परियोजनाओं में कम रुचि, व्यापक विलंब और विद्यमान परियोजनाओं के कम स्तरीय निष्पादन के कारण 2012-13 में सड़क क्षेत्र में निवेश में काफी गिरावट आ गई। इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण के आधार पर दी जाने वाली परियोजनाओं, जहां लागत राज्य वहन करते हैं, में भी प्रगति ठीक से नहीं हो रही है। इसका कारण नया कानूनी ढांचा है जिसमें निजी ठेकेदारों द्वारा परियोजना पर कार्य शुरू करने से पहले भूमि के छोटे से भाग के लिए भी पर्यावरणीय अनुमति अनिवार्य है।

सारणी II.3 कंपनी क्षेत्र - वित्तीय निष्पादन

मद	ति2:2011-12	ति3:2011-12	ति4:2011-12	ति1:2012-13	ति2:2012-13
1	2	3	4	5	6
कंपनियों की संख्या	2,241				
	वृद्धि दरें (वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत में)				
बिक्री	18.8	19.7	15.5	13.2	11.1
व्यय, जिसमें से	21.9	25.3	16.7	15.5	11.9
कच्चा माल	23.0	25.4	16.6	13.2	14.1
स्टाफ लागत	16.5	18.7	14.4	17.6	14.8
बिजली और ऊर्जा	31.4	30.5	25.4	17.7	13.9
परिचालन लाभ (ईबीआईटीडीए)	0.2	-5.1	-1.0	-4.0	10.9
अन्य आय*	41.9	67.1	51.4	29.0	50.9
मूल्यहास	11.7	10.5	11.0	9.9	9.4
सकल लाभ (ईबीआईटी)	2.8	-2.0	3.7	-3.0	19.0
ब्याज	58.5	44.4	36.9	37.0	11.4
कर प्रावधान	5.1	-1.6	2.5	-4.5	10.4
निवल लाभ	-14.2	-29.7	-5.8	-10.3	25.8
	चयनित अनुपात (प्रतिशत में)				
बिक्री की तुलना में स्टाक में परिवर्तन #	0.6	2.2	0.9	1.0	1.5
ब्याज का बोझ	29.1	28.1	26.3	32.3	27.2
ब्याज का कवरेज	13.1	12.6	13.1	12.8	13.1
बिक्री की तुलना में ईबीआईटी	11.9	11.2	12.5	11.5	12.7
बिक्री की तुलना में निवल लाभ	6.3	5.0	7.0	6.1	7.1

#: इस मद की जानकारी स्पष्टतः सूचित करने वाली कंपनियों के लिए।

*: यदि स्पष्टतः उल्लेख न किया गया हो तो अन्य आय में असाधारण आय/व्यय शामिल नहीं है।

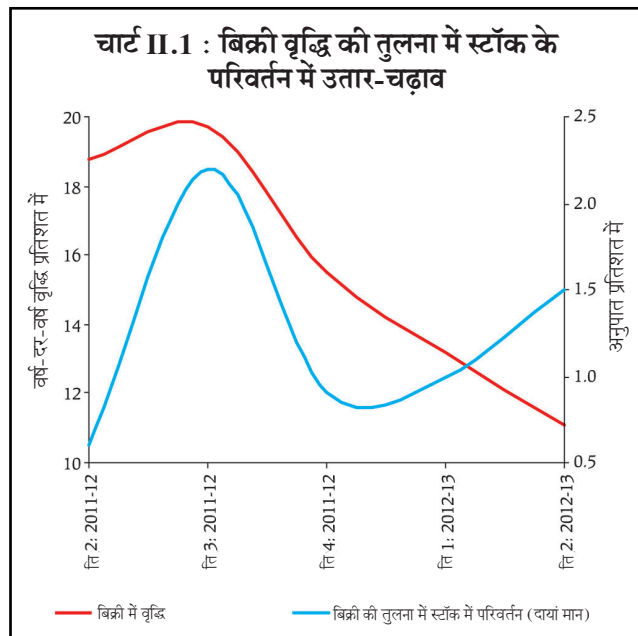
**सारणी II.4 : कारपोरेट क्षेत्र वित्तीय निष्पादन
(तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि, प्रतिशत में)**

संकेतक	2011-12			2012-13	
	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2
1	2	3	4	5	6
कंपनियों की संख्या	2,241				
बिक्री	2.8	6.4	8.6	-4.7	0.9
व्यय, जिसमें से	4.1	8.5	6.7	-4.1	0.9
कच्चा माल	0.9	8.3	9.5	-5.4	1.7
स्टाफ लागत	5.6	4.3	1.2	5.6	3.1
बिजली और ऊर्जा	0.9	3.7	5.5	6.6	-2.3
परिचालन (ईबीआईटीडीए)	-10.3	2.3	13.0	-7.4	3.7
अन्य आय	21.5	-7.8	50.0	-23.3	42.2
मूल्यहास	2.3	2.2	8.3	-3.0	1.8
सकल लाभ (ईबीआईटी)	-9.1	0.4	20.8	-12.1	11.5
ब्याज*	15.5	-3.1	13.3	8.1	-6.0
कर प्रावधान	-10.8	-4.8	14.6	-1.9	3.2
निवल लाभ	-16.0	-15.4	52.7	-17.4	17.8

*: कुछ कंपनियां निवल आधार पर ब्याज की सूचना देती हैं।

बिक्री की वृद्धि में और गिरावट आई जो कि मांग में मंदी को दर्शाती है

II.7 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों की बिक्री वृद्धि कम होकर 2012-13 की ति2 में तीन वर्षीय निम्न स्तर पर पहुंच गई (सारणी II.3)। बिक्री में गिरावट विनिर्माण, आईटी और आईटी से भिन्न सेवा क्षेत्रों, मध्यवर्ती समूहों को

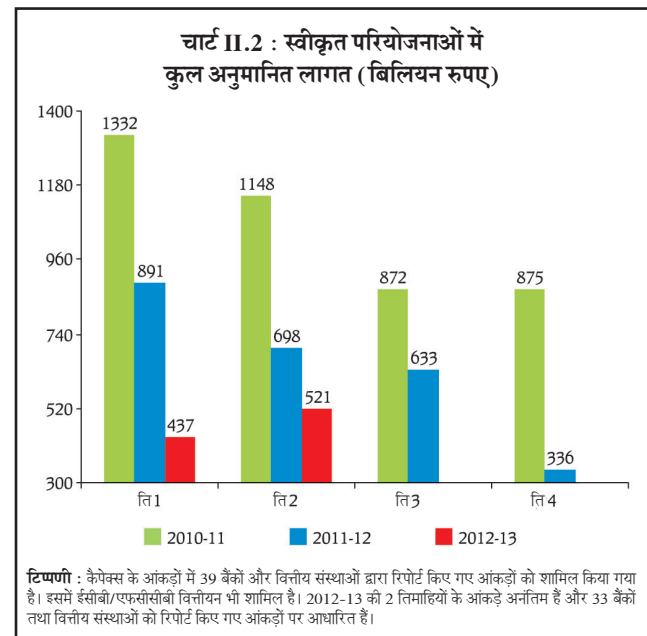


छोड़कर उपयोग-आधारित समूहों और सभी आकार समूहों में हुई थी और यह गिरावट मोटर वाहन, लोहा और इस्पात तथा वस्त्र के संबंध में अधिक तेज थी। किंतु निवल लाभ में पिछली चार तिमाहियों की प्रवृत्ति उलटते हुए 2012-13 की ति2 में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई। लाभ में वृद्धि कम आधार की थी और इसने अन्य आय तथा ब्याज भुगतान में कम वृद्धि दर को दर्शाया। इसके परिणामस्वरूप, उक्त तिमाही में लाभ मार्जिन में भी सुधार हुआ (सारणी II.4)। स्टॉक-टू-सेल अनुपात में परिवर्तन से दिखी मालसूची वृद्धि उक्त तिमाही में बढ़ गई किंतु यह 2011-12 की ति3 के हाल के शीर्ष से कम ही बनी रही (चार्ट II.1)।

II.8 2012-13 की ति3 के लिए 166 कंपनियों के प्रारंभिक परिणाम बिक्री में निरंतर गिरावट दर्शाते हैं। व्यय वृद्धि भी और कम हो गई और लाभ मार्जिन लगभग अप्रभावित रही। किंतु प्रारंभिक परिणाम कुछ ही कंपनियों के हैं और ये समग्र कंपनी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

अनुमानित परियोजना व्यय में कुछ वृद्धि हुई

II.9 39 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर और साथ ही बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के आधार पर 2012-13 ति2 में स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत में कुछ वृद्धि हुई। किंतु स्वीकृत सहायता की राशि पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में काफी कम थी (चार्ट II.2)।



टिप्पणी : कैपेक्स के आंकड़ों में 39 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों को शामिल किया गया है। इसमें ईसीबी/एफसीसीबी वित्तियन भी शामिल है। 2012-13 की 2 तिमाहियों के आंकड़े अर्न्ततम हैं और 33 बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को रिपोर्ट किए गए आंकड़ों पर आधारित है।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की सहायता के लिए नए नीतिगत उपाय

II.10 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण योजना समिति (अध्यक्ष: डॉ. विजय एल. केलकर) की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने अक्टूबर 2012 में संशोधित राजकोषीय योजना की घोषणा की। संशोधित योजना के अनुसार 2012-13 का सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.3 प्रतिशत अनुमानित है जबकि बजट अनुमान 5.1 प्रतिशत का है। सरकार की राजकोषीय सुदृढ़ीकरण योजना के अनुसार राजकोषीय घाटा 2013-14 में कम होकर 4.8 प्रतिशत रहेगा और उसके बाद प्रतिवर्ष 0.6 प्रतिशत कम होकर 2016-17 में जीडीपी के 3.0 प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।

II.11 सरकार ने घाटा कम करने और सरकारी वित्त को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक उपाय किए। सरकार ने जनवरी 2013 में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में डीजल के मूल्यों से आंशिक रूप से विनियमन हटाया जिससे थोक ग्राहकों के लिए मूल्य के पूरे समायोजन की और अन्य के लिए क्रमिक वृद्धि की अनुमति प्राप्त हुई। दूसरी ओर, प्रति परिवार सब्सिडीयुक्त एलपीजी सिलिंडर की वार्षिक आपूर्ति बढ़ाकर नौ की गई जो कि सितंबर 2012 की घोषणा के अनुसार छह थी। इन उपायों से राजकोषीय असंतुलन में कमी आने की संभावना है हालांकि चालू वित्तीय वर्ष में इसका प्रभाव कम रहने की संभावना है।

II.12 बजट लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर नए सिरे से बल देना, योजना तथा योजनेतर व्यय में कटौती और सब्सिडी के लिकेजों को कम करने के लिए प्रत्यक्ष नकदी अंतरण पर अधिक निर्भरता कुछ ऐसे उपाय थे जो कि राजकोषीय घाटा कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण थे। किंतु सरकार ने सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के विनिधान बरकरार रखे ताकि गरीबों को संरक्षण मिलता रहे। कर सुधारों के संबंध में, माल और सेवा कर लागू करने और प्रत्यक्ष कर संहिता की समीक्षा करने की प्रतिबद्धता घोषित की गई। अभी हाल ही में सरकार ने दोहराया है कि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय को 33 प्रतिशत तक सीमित रखा जाएगा और यह कि मार्च के दौरान इसे 15 प्रतिशत रखा जाएगा ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय व्यय की अधिकता न रहे।

II.13 राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के और अधिक उपाय अल्पकालिक संदर्भ में आवश्यक होंगे। केलकर समिति ने इस संदर्भ में अनेक सिफारिशों की हैं। उदाहरण के लिए, अगले दो या तीन वर्षों में सरकार के अप्रयुक्त या कम प्रयुक्त भूमि संसाधनों के मुद्रिकरण से संसाधन जुटाए जा सकते हैं। इन संसाधनों का उपयोग विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के वित्तपोषण के लिए किया जा सकता है। किंतु ऐसे नवोन्मेशी उपायों की समीक्षा करनी होगी क्योंकि आस्तियों के विक्रय से राजकोषीय स्थिति में संरचनात्मक सुधार होने में सहायता नहीं मिलती।

मंदी से राजस्व प्रभावित होने से राजकोषीय घाटा उच्च बना रहा

II.14 चालू वर्ष के पहले आठ महीनों के दौरान राजकोषीय घाटा जीडीपी के 4.1 प्रतिशत या बजट अनुमान का 80.4 प्रतिशत था (सारणी II.5)। राजस्व घाटा जीडीपी के 3.1 प्रतिशत था जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कुछ ही कम था। वर्तमान प्रवृत्ति के चलते कर राजस्व में काफी कमी और अनुमानित स्पेक्ट्रम प्राप्तियों में कुछ कमी की संभावना है। अनुमानित विनिवेश आय की प्राप्ति काफी हद तक बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। किंतु सरकार वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान योजना और योजनेतर - दोनों व्ययों पर नियंत्रण करके 5.3 प्रतिशत का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास कर रही है।

मंद वृद्धि राजस्व वसूली के मार्ग की बाधा बनी हुई है

II.15 राजस्व वसूली अप्रैल-नवंबर 2012 के दौरान 47.6 प्रतिशत पर मंद बनी रही (पिछले वर्ष 49.7 प्रतिशत)। कंपनी कर और उत्पाद शुल्क की वसूली में वृद्धि में कमी बनी रही जिसका कारण वृद्धि में निरंतर मंदी बनी रहना था जबकि सीमा शुल्क की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जो कि आयात में गिरावट को दर्शाता है। किंतु निजी आय कर के अंतर्गत वसूली में तेजी बनी रही जिसका आंशिक कारण पिछले वर्ष की तुलना में धन वापसी में कमी आना था। बजट अनुमानों के 46.3 पर करेतर राजस्व प्राप्तियां भी पिछले वर्ष की इसी अवधि के 57.7 प्रतिशत की तुलना में काफी कम अर्थात् 46.3 प्रतिशत था जिसका कारण स्पेक्ट्रम नीलामी को कम प्रतिसाद मिलना और नीलामी की प्राप्तियों की गति मंद रहना था।

सारणी II.5 : अप्रैल-नवम्बर 2012 के दौरान केन्द्र सरकार के वित्त

(₹ बिलियन)

मद	2012-13 के बजट अनुमान	अप्रैल-नवम्बर		बजट अनुमान की तुलना में प्रतिशत		वृद्धि दर (प्रतिशत)	
		2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
1. राजस्व प्रप्तियां (i+ii)	9356.9	3928.1	4458.2	49.7	47.6	-17.6	13.5
i) कर राजस्व (निवल)	7710.7	3204.7	3696.0	48.2	47.9	8.0	15.3
ii) करेतर राजस्व	1646.1	723.4	762.2	57.7	46.3	-59.8	5.4
2. गैर-ऋण पूंजी प्रप्तियां	416.5	145.1	89.0	26.4	21.4	-47.1	-38.7
3. गैर-योजना व्यय	9699.0	5394.2	6242.6	66.1	64.4	12.4	15.7
जिसमें से							
i) ब्याज का भुगतान	3197.6	1659.1	1828.6	61.9	57.2	23.3	10.2
ii) खाद्यान्न सब्सिडी	750.0	440.7	620.0	72.8	82.7	-12.3	40.7
iii) उर्वरक सब्सिडी	609.7	450.4	552.9	90.1	90.7	17.7	22.8
iv) पेट्रोलियम सब्सिडी	435.8	233.0*	403.0	98.4	92.5	49.1	72.9
4. योजना व्यय	5210.3	2212.8	2433.9	50.1	46.7	4.9	10.0
5. राजस्व व्यय	12861.1	6732.7	7653.2	61.4	59.5	9.1	13.7
6. पूंजीगत व्यय	2048.2	874.2	1023.3	54.4	50.0	18.4	17.0
7. कुल व्यय	14909.3	7606.9	8676.5	60.5	58.2	10.1	14.1
8. राजस्व घाटा	3504.2	2804.6	3195.0	91.3	91.2	100.1	13.9
9. सकल राजकोषीय घाटा	5135.9	3533.7	4129.3	85.6	80.4	89.5	16.9
10. सकल प्राथमिक घाटा	1938.3	1874.6	2300.7	129.4	118.7	260.7	22.7

*: यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के योजनेतर व्यय से संबंधित है जिसमें मुख्य रूप से, संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण कम वसूली के लिए, तेल विपणन कंपनियों को एपीएम के बाद की सब्सिडी और मुआवजा शामिल है, यह अन्य योजनेतर व्यय की वसूली राशि के अलावा है।

स्रोत : लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय

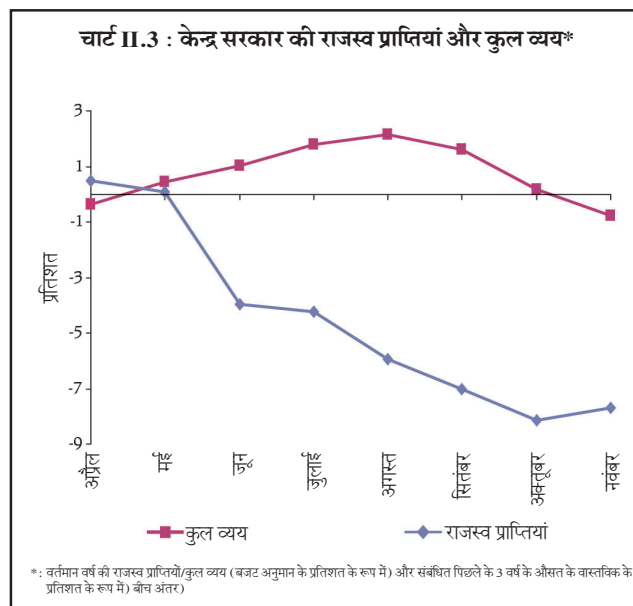
कुल व्यय में कमी आने के बावजूद योजनेतर व्यय से निरंतर दबाव बना रहा

II.16 अप्रैल-नवम्बर 2012 के दौरान सरकार का कुल व्यय बजट अनुमान के 58.2 प्रतिशत के साथ कम था (पिछले वर्ष 60.5 प्रतिशत)। व्यय में गिरावट सितंबर 2012 से अधिक स्पष्ट रही है जिसमें चालू वर्ष के व्यय (बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में) और संबंधित तीन-वर्षीय औसत (वास्तविक के प्रतिशत के रूप में) के बीच का अंतर कम होता गया जो कि व्यय नियंत्रण के सरकारी प्रयासों को दर्शाता है (चार्ट II.3)।

II.17 किंतु मुख्यतः योजनेतर राजस्व व्यय के कारण 2012-13 में सरकार का कुल व्यय बजट अनुमान से अधिक हो जाने की संभावना है। 16.7 प्रतिशत के साथ अप्रैल-नवम्बर 2012 के दौरान योजनेतर राजस्व व्यय वृद्धि 6.1 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि से काफी अधिक थी।

राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता चिंता का कारण बनी रही

II.18 योजना और पूंजी व्यय में काफी कटौती और विनिवेश आय जैसी अस्थायी प्राप्तियों पर निर्भरता से



राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। अप्रैल-नवंबर 2012 के दौरान बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में योजना व्यय और पूंजी व्यय पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था। बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में योजना व्यय बिजली, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास और महिला तथा बाल विकास जैसे प्रमुख मंत्रालयों/विभागों के संबंध में कम था। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर में कम सरकारी निवेश से वृद्धि प्रभावित हो सकती है। जहां व्यय की गुणवत्ता चिंता का विषय है, वहीं विनिवेश आय तथा स्पेक्ट्रम नीलामी जैसी एकबारगी प्राप्तियों पर अधिक निर्भरताके माध्यम से राजकोषीय वृद्धि दीर्घकालिक नहीं हो सकती।

अतिरिक्त बाजार उधार से इस वर्ष बचा जा सकता है किंतु और अधिक उपायों की आवश्यकता है

II.19 सरकार ने अनुदान के लिए पहली प्रतिपूरक मांग की घोषणा की जिसमें ₹308 बिलियन का निवल नकदी परिव्यय शामिल है जो कि मुख्यतः तेल विपणन कंपनियों की अनुमानित कम वसूली के संदर्भ में आंशिक मुआवजे (₹285

बिलियन) और एयर इंडिया में मुद्रा आपूर्ति (₹20 बिलियन) के लिए थी। इस अतिरिक्त व्यय के लिए अतिरिक्त बाजार उधार नहीं लिया जाएगा। किंतु अब तक किया गया सब्सिडी का प्रावधान अपर्याप्त है।

निवेश मांग का पुनरुज्जीवन आर्थिक सुधार का आधार है

II.20 सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने की प्रतिबद्धता की है। किंतु यदि यह कटौती मुख्यतः योजना/पूंजी शीर्षों में की जाएगी तो यह राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की गुणवत्ता संबंधी चिंता उत्पन्न करेगी। सरकार द्वारा घोषित सुधार लागू होने पर निवेश के वातावरण में सुधार होगा जिससे वृद्धि के पुनरुज्जीवन में सहायता मिलेगी। निजी निवेश बढ़ाने में सरकारी निवेश में वृद्धि करना और निजी निवेश को मंद करने वाली संरचनात्मक बाधाओं को हटाना अर्थव्यवस्था को वर्तमान मंदी से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है।